आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरूवार 12.06.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं।
- रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए नए नियम घोषित किए। पहली जुलाई से आधार और ओटीपी सत्यापन अनिवार्य।
- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इस वित्तीय वर्ष के लिए पांच हजार दो सौ बारह मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- देहरादून में सरकारी स्कूलों को आधुनिक और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में ''प्रोजेक्ट उत्कर्ष'' के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। श्री बिरला ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि यह प्रशिक्षण आपके जीवन में नया दृष्टिकोण, नया विचार और कार्य करने की प्रेरणा देगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष रूप से राज्य प्रशासनिक सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है।

तत्काल टिकट नियम

भारतीय रेल ने तत्काल टिकट के लिए नए नियमों की घोषणा की है। पहली जुलाई से केवल वे लोग ही भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम –आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे, जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। 15 जुलाई से यह नियम आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने पर भी लागू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से बुक कराने और यात्रियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला किया गया है।

सहायता निधि

आपदा या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को अब राज्य सरकार से तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि' की नियमावली को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाना है। इस सहायता से जरूरतमंदों को रहने, खाने, इलाज, पढ़ाई और रोजगार जैसे कार्यों में मदद दी जाएगी। जिनका आमदनी का जरिया प्रभावित हुआ हो, उन्हें भी लाभ मिलेगा। योजना के लिए धनराशि अंग्रेजी शराब की बिक्री पर सैस लगाकर जुटाई जाएगी।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि योजना की खास बात इसकी तत्काल मदद व्यवस्था है। पात्र व्यक्ति के आवेदन पर ब्लॉक स्तर की टीम पांच हजार रुपये तक की सहायता तुरंत दे सकेगी। दस हजार से पच्चीस हजार रुपये की मदद जिला समिति 15 दिन में स्वीकृत करेगी। जरूरत अधिक होने पर राज्य स्तरीय समिति 5 लाख रुपये तक की सहायता दे सकेगी।

योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन, दवा से जुड़ी किट, अस्पताल पहुंचाने की सुविधा, रहने–खाने की व्यवस्था और मेधावी छात्राओं को पढ़ाई में मदद मिलेगी। मनरेगा या निर्माण स्थलों पर काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

सत्यापन रिपोर्ट

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक सीमित करने के लिए देहरादून प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में फर्जी राशन और आयुष्मान कार्ड के मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए व्यापक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

श्री बंसल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से 15 दिनों के भीतर आयुष्मान कार्ड धारकों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, जिला पूर्ति अधिकारी को तीन लाख 87 हजार से अधिक राशन कार्डधारकों का विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी को देने और टीमें गठित कर घर–घर जाकर सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जिले में सिर्फ 35 हजार 393 राशन कार्ड सत्यापित हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अपात्र कार्डधारकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे से सिर्फ उन्हीं को राशन कार्ड मिलेगा जो नियमों के अनुसार पात्र होंगे।

यू०जे०वी०एन०एल लक्ष्य

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड– यू०जे०वी०एन०एल ने इस वित्तीय वर्ष के लिए पांच हजार दो सौ बारह मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित यूजेवीएनएल की 126वीं बोर्ड बैठक में यह लक्ष्य तय किया गया।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में निगम के प्रदर्शन और मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के सापेक्ष उपलब्धियों की समीक्षा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025–26 के लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया गया।

बैठक में सिरकारी–भयोल–रूपसिया बगड़ परियोजना के सिविल पैकेज को हाइड्रो पैकेज में शामिल करने का अनुमोदन दिया गया। मद्महेश्वर परियोजना की समय सीमा को भी विस्तारित किया गया। वहीं, मनेरी भाली परियोजना में रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल से सर्वे कराए जाने को मंजूरी दी गई।

प्रोजेक्ट उत्कर्ष

देहरादून में सरकारी स्कूलों को आधुनिक और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में ''प्रोजेक्ट उत्कर्ष'' के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत जिले के 168 माध्यमिक विद्यालयों में 884 बड़े एलईडी टीवी लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए जैम पोर्टल पर बिड अपलोड कर क्रय आदेश जारी कर दिया गया। यह कार्य खनिज न्यास, जिला योजना और सीएसआर फंड के माध्यम से जुटाए गए 6 करोड़ रुपये की सहायता से किया जा रहा है। स्कूलों को डिजिटल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। पहले से ही इन स्कूलों में वाइट बोर्ड, कक्षा में दो एलईडी लाइट, खेल के मैदान, रसोईघर, बिजली, पुस्तकालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं। अब प्रत्येक कक्षा में टीवी लगाए जाने से छात्रों को डिजिटल कक्षाओं का लाभ मिलेगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल इससे पहले नैनीताल और अल्मोड़ा में भी इसी मॉडल के तहत सभी सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बना चुके हैं। देहरादून में भी उन्होंने इस दिशा में ठोस पहल करते हुए खनिज न्यास से तीन दशमलव छह–सात करोड़ की धनराशि शिक्षा विभाग को डिजिटल शिक्षा के लिए दी है। ओएनजीसी और हुडको ने भी जिलाधिकारी के इस प्रयास में भागीदारी निभाते हुए फर्नीचर, एलईडी बल्ब और स्क्रीन उपलब्ध कराकर सहयोग दिया है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान

विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत ऊधमसिंह नगर जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शांतिपुरी में कृषक संगोष्ठि का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, डेरी, मत्स्य, रेशम, फल प्रसंस्करण, रीप, स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्टॉल लगाकर जानकारियां दी गयी। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि

अभियान के तहत किसानों को उनके द्वार आकर कृषि से संबंधित योजनाओं और कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है, ताकि कृषक उन्नत बीजों के साथ ही कृषि के नये तकनीको को अपनाकर लाभ उठा सके व अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकें।